



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष १०, अंक ४]

बुधवार, जानेवारी ३१, २०२४/माघ ११, शके १९४५

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले

(भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)

वैधानिक नियम व आदेश; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जानेवारी २०२४

क्रमांक जीवका-२०२३/प्र.क्र.७१/नापु. २८.- ग्राहक बाबी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडून असाधारण राजपत्र, भाग II-खण्ड ३ उप-खंड (ii) मध्ये दि. ८ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुनःप्रकाशित करण्यात येत आहे.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, ८ दिसम्बर, २०२३

का.आ. ५२९२(अ).- केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के आदेश असाधारण, भाग (II) धारा-३, उप-धारा (ii) में दिनांक १२ जून, २०२३ के का. आ. सं. २५६६ (अ) के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ २ (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(१)

२ (i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ दिनांक ३१ मार्च, २०२४ तक की अवधि के लिए गेहूं :

- व्यापारी/थोक विक्रेता : १००० टन;
- रिटेलर : प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए ५ टन;
- बिग चेन रिटेलर: प्रत्येक आउटलेट के लिए ५ टन और उनके सभी डिपुओं पर १००० टन;
- प्रोसेसर्स : मासिक स्थापित क्षमता का ७०% को २०२३-२४ के शेष महीनों से गुणा करके।

[फा. सं. ३/१/२००७- नीति -III]

ऋचा शर्मा,
अपर सचिव.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)

Order

New Delhi, the 8th December, 2023

S.O. 5292(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Department of Food and Public Distribution published in the Gazette of India, Extraordinary, Part(II) Section-3, sub section(ii) *vide* number S.O. 2566(E) dated the 12th June, 2023 namely.

In the said Order, Paragraph 2(i) shall be replaced as under :—

“2 (i) Wheat for a period up to 31st March 2024 with following stock limits for all States and Union Territories :—

- Traders/Wholesalers: **1000 MT** ;
- Retailers: **5 MT** for each Retail outlet
- Big Chain Retailers: **5 MT** for each outlet and **1000 MT** at all their depot,
- Processors: **70% of monthly** installed capacity **multiplied by remaining months of 2023-24.**

[F. No. 3/1/2007 Py-III]
RICHA SHARMA,
Addl. Secy.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

ता.मा. कोळेकर,
शासनाचे सहसचिव.